PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Deccan Herald, Bangalore
Sunday 1st March 2015, Page: 5
Width: 12.57 cms, Height: 8.29 cms, a4, Ref: pmin.2015-03-02.14.15

Relief for textile industry

BENGALURU: The textile manufacturers heaved a sigh of relief when the Budget did not have any mention of imposition of excise on readymade garments.

Talking to *Deccan Herald*, former president of Karnataka Hosiery and Garment Association Sajjan Raj Mehta said: "At the time of Budget, rumours of imposition of excise on readymade garments were going around...Thank god nothing came up."

With the imposition of 10 per cent excise duty on branded products by former finance minister, the textile industry had been dealt with a heavy blow. India, the second largest producer of textiles and garments in the world, sought to phase out the CST from 2 per cent to zero per cent—a trend continued in Jaitley's Budget.

"The hike in service tax from 12.36 per cent to 14 per cent is a clear indication that it will add to the existing high inflation and for which common people will be soft target," Mehta said.

On the other hand, Texport Syndicate India Director Avinash Misar said, "I find the Budget very balanced and growth oriented. Reduction in corporate tax from 30 per cent to 25 per cent is a very bold move. This clearly indicates that government means business and wishes that investment grows. Such a radical move is very encouraging for growth. It is a big step ahead."

"Excise duty exemption on garments in domestic sector is a step in the right direction. This would give a good impetus to domestic brands and this would see a growth in business," Misar added. It provides direct employment to over 3.5 crore people.

DH News Service

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Monday 2nd March 2015, Page: 5
Width: 7.88 cms, Height: 4.41 cms, a4, Ref: pmin.2015-03-02.31.32

लखनऊ में हैंडलूम प्रदर्शनी सफल

नई दिल्ली (ब्यूरो)। एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेशंस एंड एपेक्स सोसाइटीज ऑफ हैंडलूम्स की ओर से कैसर बाग बारादरी लखनऊ में प्रदर्शनी ताना-बाना में हैंडलूम, सिल्क और कॉटन के कपड़ों की बिक्री की जा रही है। प्रदर्शनी में बनारस, बिहार, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आदि से आए कलाकारों ने 63 स्टाल लगाए हैं। आकाश के प्रभारी जेपी कोठारी ने बताया कि यहां अब तक 12 लाख से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। प्रदर्शनी का समापन 3 मार्च को होगा।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Monday 2nd March 2015, Page: 11
Width: 13.44 cms, Height: 14.08 cms, a4, Ref: pmin.2015-03-02.31.79

रोजगारपरक टेक्सटाइल क्षेत्र की बजट में हुई अनदेखी

राजीव कुमार

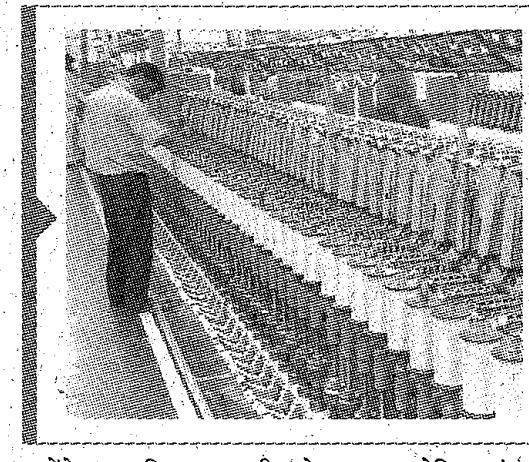

टफ मद में मात्र 1,520 करोड़ रुपये का आवंटन, 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की थी मांग

कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराता है टेक्सटाइल क्षेत्र

नई दिल्ली। आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के लिए पेश आम बजट में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र की पूरी अनदेखी की गई। टेक्सटाइल क्षेत्र के घरेलू कारोबारियों से लेकर निर्यातकों तक ने बजट को अपनी उम्मीदों के प्रतिकूल बताया है। टेक्सटाइल क्षेत्र के घरेलू कारोबारी खासकर यार्न के उत्पादकों के मुताबिक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ) के मद में आवंटन कटौती से टेक्सटाइल क्षेत्र के उत्पादकों को काफी निराशा हाथ लगी है।

चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सरकार की तरफ से टफ स्कीम में 1,864 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में मात्र 1,520 करोड़ रुपये का आवंटन टफ स्कीम में किया गया है। कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सिटी) के चेयरमैन प्रेम मलिक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की विगत तीन तिमाही से टफ स्कीम के तहत टेक्सटाइल उद्यमियों को भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि टफ स्कीम के तहत टेक्सटाइल उद्यमियों को भुगतान नहीं मिलने से टेक्सटाइल क्षेत्र में तकनीक अपग्रेडेशन के मद में होने वाले निवेश पर विपरीत असर पड़ रहा है। साउथ इंडियन मिलर्स एसोसिएशन (एसईएमए) के महासचिव के. सेल्वाराजु के मुताबिक टफ स्कीम के तहत उद्यमियों के बकाए का भुगतान करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से आगामी वित्त वर्ष के लिए टफ मद में 3,000 करोड़ रुपये देने की मांग की थी। लेकिन मंत्रालय की मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सिटी के महासचिव डी.के. नायर के मुताबिक बजट में टेक्सटाइल को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया जबकि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार का सृजन टेक्सटाइल क्षेत्र में होता है। टेक्सटाइल मंत्री संतोष गंगावार ने हाल ही में कहा था कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं होंगी। राजु कहते हैं कि मैन मेड फाइबर पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती की मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Monday 2nd March 2015, Page: 5
Width: 8.26 cms, Height: 20.96 cms, a4, Ref: pmin.2015-03-02.33.78

विकास की नींव रखी गई बजट में : गंगवार

बरेली, 1 मार्च (जनसत्ता)। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस बार रेल और आम बजट भले ही लोकलुभावन न हो, लेकिन इनके जरिए विकास की मजबूत नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के रास्ते पर चलते ही लोगों को भी समझ आ जाएगा और विपक्षियों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास में विश्वास रखती है। इसलिए यूपीए सरकार की तरह बजट में रेवड़ियां बांटने का काम नहीं किया गया है।

केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्षी दल नाहक बजट की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे का विकास किए बिना सही मायने में किसी क्षेत्र में विकास मुमकिन नहीं है। इसलिए रेल बजट में सिर्फ नई ट्रेनों का एलान करने की परंपरा से बचते हुए ढांचागत विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से आम लोगों और उद्योग जगत दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस समय तो एक्सप्रेस ट्रेनें भी कार की रफ्तार से ही चल रही है। इसी तरह आम बजट में भी दीर्घकालीन विकास और गरीबी को हटाने के सोच के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही मनरेगा की आलोचना करते हुए इसे कांग्रेस का स्मारक करार दिया लेकिन इसके बजट में भी पहले के मुकाबले पांच हजार करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा को अब नए रूप में चला कर इससे ग्रामीण विकास कराया जाएगा। पहले की तरह सिर्फ गड्ढे खुदवा कर धन बर्बाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओ, पेंशन और बीमा आदि से गरीबो को जोड़ने की कोशिश की गई है। इन योजनाओं से आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी।

आम बजट में उत्तर प्रदेश से भेदभाव किए जाने के सपा नेताओं के आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर मोदी सरकार अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार कोयला और दूसरे खनिजों के खनन पर मिलने वाली रॉयल्टी में राज्यों का हिस्सा बढ़ा कर 62 फीसद किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्य सरकारें खुश हैं। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बरेली और दूसरे जिलो में हस्तशिल्प के क्लस्टर पहले से बन रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां कहीं भी कहेंगे, वहां टैक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां के सामाजिक संगठनों की मांग को पूरा कराने के लिए दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के लिए ट्रेनें भी जल्द शुरू कराई जाएगी।

उधर विपक्षी दलों के नेताओं और उद्यमियों ने बजट को निराशाजनक बताया है। बसपा के जोनल समन्वयक ब्रह्म स्वरूप सागर ने कहा कि इस बजट में पूंजीपतियों के हित साधने के प्रयास किए गए हैं। यह महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। आम लोग तो अच्छे दिनों का इंतजार करते ही रह जाएंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामदेव पांडेय ने कहा कि इस बजट से किसानों और आम लोगों को निराशा हुई है। मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष भारत भूषण शील ने कहा कि सेवाकर बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेता अवधेश अग्रवाल ने कहा कि आयकर छूट की सीमा बढ़ने की आस में बैठे छोटे व्यापारियों को बजट ने निराश किया है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan Times, Delhi
Monday 2nd March 2015, Page: 16
Width: 4.23 cms, Height: 7.36 cms, a4, Ref: pmin.2015-03-02.42.202

Craft of Living Exhibition inaugurated in Delhi

A. Madhukumar Reddy, Joint Secy, Ministry of Textiles inaugurated the Craft of Living Exhibition at Central Cottage Industries Emporium in New Delhi. The exhibition comprises of diversified products and a large variety of items such as wooden panel, antique oil lamps, tanjore paintings, etc. The exhibition will be on till February 28, 2015.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

MINT, Delhi
Monday 2nd March 2015, Page: 10
Width: 28.13 cms, Height: 22.22 cms, a3r, Ref: pmin.2015-03-02.46.11

THE TOP 35 MINISTRIES/DEPARTMENTS

	Ministry/department	2015-16 Allocation (₹cr)	Change (%) *	Under-spending or over-spending in 2014-15 (%) ** Overall (%)	In capital expenditure	In revenue expenditure
1	Defence services	246,727	11.0	-2.9	-13.3	4.5
2	Food and public distribution	125,212	1.7	6.5	-50.0	6.6
3	Fertilizers	73,048	2.9	-2.9	-99.6	-2.8
4	Home affairs	65,651	13.6	-5.8	-42.3	1.4
5	Defence (civil estimates)	63,353	15.4	-2.3	-26.2	-1.6
6	Road transport and highways	42,842	39.7	-3.3	-5.4	8.4
7	Railways	40,000	32.9	0.0	0.0	0.0
8	Petroleum and natural gas	30,126	-52.0	-1.3	See note***	-5.0
9	Expenditure	29,871	7.7	2.5	-26.7	2.5
10	Higher education	25,700	10.3	-8.5	0.0	-0.5
11	Financial services	24,867	15.1	-0.1	-24.8	47.9
12	Economic affairs	17,240	19.8	-14.3	-61.3	-5.4
13	External affairs	14,967	18.6	-14.3	-24.9	-7.0
14	Telecommunications	13,475	29.8	-28.5	-77.9	4.0
15	Urban development	13,193	24.1	-17.9	-22.7	-3.2
16	Health and family welfare	11,358	10.8	-3.9	-46.9	2.7
17	Atomic energy	10,912	22.4	-14.7	-25.3	4.2
18	Rural development	7,493	20.2	-16.8	0.0	-16.8
19	Space	7,388	26.8	-19.5	-33.2	7.1
20	Posts	7,139	6.9	-13.4	-68.7	-9.4
21	Power	6,726	20.1	-41.3	-33.3	4.0
22	Agriculture research and education	6,320	29.4	-20.5	0.0	-1.9
23	Agriculture and cooperation	6,204	9.8	-8.8	-38.1	-8.5
24	School education and literacy	6,153	3.6	-5.1	0.0	-5.1
25	Commerce	5,092	-0.6	1.4	29.0	-0.4
26	Textiles	4,275	13.9	-27.7	-46.2	-27.2
27	Scientific and industrial research	4,031	18.6	-8.3	-56.8	12.0
28	Labour and employment	3,967	15.8	-12.6	-0.9	-8.8
29	Science and technology	3,836	32.4	-18.2	-67.7	-17.9
30	Information and broadcasting	3,711	16.8	-4.2	11.1	-4.3
31	Civil aviation	3,342	-50.2	-9.0	-11.0	6.1
32	Micro, small and medium enterprises	3,007	4.2	-22.1	0.0	2.6
33	Law and justice	2,961	172.6	-9.9	0.0	0.0
34	Social justice and empowerment	2,793	47.3	-31.8	43.3	9.0
35	Electronics and information technology	2,630	16.0	-28.6	-62.1	-26.4

* Budget estimates 2015-16 versus revised estimates 2014-15, ** Revised estimates 2014-15 versus budget estimates 2014-15,*** Increase of 239,900%: ₹2,400 crore versus ₹1 crore. Since the number is too large to show in the graphic, it has been placed in the footnote

howindialives.com is a Delhi-based start-up that is developing a search engine for public data to make it more accessible to decision-makers

Graphics by Ahmed Raza Khan/Mint

Source: Budget documents for 2015-16